

INDIA-EU RELATIONS

Why in the News?

India celebrates 60 years of diplomatic relations with the European Union (EU).

Key Points

Recent developments in India-EU ties

A Brief Timeline

- 1962:** Establishment of diplomatic relations between India and the European Economic Community (EEC)
- 1994:** A cooperation agreement signed which took the bilateral relationship beyond trade and economic cooperation.
- 2000:** The Joint Declaration of the First India – EU Summit
- 2004:** Strategic Partnership at the Fifth India – EU Summit
- 2005:** Adoption on Joint Action Plan on Maritime Cooperation
- 2020:** India–EU Strategic Partnership: Roadmap to 2025

Areas of cooperation

- **Economic Partnership:** Bilateral trade between the two surpassed \$116 billion in 2021-22.
 - The EU is India's second largest trading partner after the U.S., and the second largest destination for Indian exports.
 - India enjoys preferential tariffs under EU Generalised system of Preference(GSP).

- **Energy:** Finalised civil nuclear cooperation agreement (European Atomic Energy Community)
- **Green Strategic Partnership:** India and Denmark aims to address climate change, biodiversity loss and pollution
 - The India-Nordic Summit in May focused on green technologies
- **Defence sector:** India and the EU regularly conduct joint military and naval exercises which reflects their commitment to a free, open, inclusive and rules-based order in the Indo-Pacific.
 - The first maritime security dialogue in 2021 focused on cooperation in maritime domain awareness, capacity-building, and joint naval activities.
 - France's on-time delivery of 36 Rafale fighter jets and willingness to offer Barracuda nuclear attack submarines to the Indian Navy reflects the growing level of trust.
- **Science and technology:** It focus on areas such as healthcare, Artificial Intelligence, and earth sciences.

Other areas of cooperation

- Effective implementation of the Paris agreement.
- Start-up and innovation ecosystem across India and Europe.
- Offshore wind and solar infrastructure
- Clean Ganga initiative

Challenges

- Differing opinions and divergent interests: India's reluctance to condemn Russia for the Ukraine crisis is not agreed upon by the EU,
- For both India and the EU, China forefronts a major challenge that requires specific attention.
- There is an ambiguity on the EU's strategy in tackling the rise of China. Delay in signing proposed Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA).
- Fit for 55 agenda, presents challenges for Indian industries.
 - It is EU 2030 goal of reducing emissions by 55% from 1990 levels.

Way Forward

- India's economic, political and demographic weight could be leveraged by the EU to counterbalance China's influence across the region.
- For that, the resumption of the ambitious India-EU free trade and investment agreement in 2021 is a step in the right direction.
- India and the EU should renegotiate the trade deal and trust each other not only to promote rules-based multilateral order in the Indo-Pacific but also to achieve other strategic ambitions.
- With the rise of multipolarity both sides can elevate their strategic partnership to find solutions for impending geopolitical challenges.
- Need to build cooperation on data protection and regulation.
- Human connectivity and digital connectivity can be the newer areas of cooperation.

भारत-यूरोपीय यूनियन संबंध

खबरों में क्यों?

भारत, यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ 60 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहा है।

प्रमुख बिंदु

भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों में हाल के घटनाक्रम

एक संक्षिप्त समयरेखा:

A Brief Timeline

- 1962:** Establishment of diplomatic relations between India and the European Economic Community (EEC)
- 1994:** A cooperation agreement signed which took the bilateral relationship beyond trade and economic cooperation.
- 2000:** The Joint Declaration of the First India – EU Summit
- 2004:** Strategic Partnership at the Fifth India – EU Summit
- 2005:** Adoption on Joint Action Plan on Maritime Cooperation
- 2020:** India–EU Strategic Partnership: Roadmap to 2025

सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक साझेदारी:** दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 116 अरब डॉलर को पार कर गया।
 - यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
 - भारत को ईयू जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) के तहत प्राथमिकता टैरिफ प्राप्त है।

- **ऊर्जा:** असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को अंतिम रूप दिया (यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय)
- **हरित सामरिक साझेदारी:** भारत और डेनमार्क का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण को दूर करना है।
 - मई में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हरित प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था।
- **रक्षा क्षेत्र:** भारत और यूरोपीय संघ नियमित रूप से संयुक्त सैन्य और नौसैनिक अभ्यास करते हैं जो इंडो-पैसिफिक में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
 - 2021 में पहला समुद्री सुरक्षा संवाद समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, क्षमता निर्माण और संयुक्त नौसैनिक गतिविधियों में सहयोग पर केंद्रित था।
 - फ्रांस द्वारा 36 राफेल लड़ाकू जेट की समय पर डिलीवरी और भारतीय नौसेना को बाराकुडा परमाणु हमले की पनडुब्बियों की पेशकश करने की इच्छा विश्वास के बढ़ते स्तर को दर्शाती है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** यह स्वास्थ्य देखभाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

सहयोग के अन्य क्षेत्र:

- पेरिस समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन।
- भारत और यूरोप में स्टार्ट-अप और इनोवेशन इकोसिस्टम।
- अपतटीय पवन और सौर अवसंरचना
- स्वच्छ गंगा पहल

चुनौतियां

- **अलग-अलग राय और अलग-अलग हित:** यूक्रेन संकट के लिए रूस की निंदा करने के लिए भारत की अनिच्छा यूरोपीय संघ को स्वकार्य नहीं है।
- भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए, चीन एक बड़ी चुनौती है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- चीन के उदय से निपटने में यूरोपीय संघ की रणनीति पर अस्पष्टता है।
- प्रस्तावित व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर हस्ताक्षर करने में देरी।
- फिट फॉर 55 एजेंडा, भारतीय उद्योगों के लिए चुनौतियां पेश करता है।
 - इसके अंतर्गत 1990 के स्तर से उत्सर्जन को 55% तक कम करने का EU 2030 लक्ष्य है।

आगे बढ़ने की राह

- पूरे क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा भारत के आर्थिक, राजनीतिक और जनसांख्यिकीय भार का लाभ उठाया जा सकता है।
- उसके लिए, 2021 में महत्वाकांक्षी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार और निवेश समझौते को फिर से शुरू करना सही दिशा में एक कदम है।
- भारत और यूरोपीय संघ को व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करनी चाहिए और न केवल भारत-प्रशांत में नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अन्य रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे पर भरोसा करना चाहिए।
- बहुध्रुवीयता के उदय के साथ दोनों पक्ष आसन्न भू-राजनीतिक चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा सकते हैं।
- डेटा संरक्षण और विनियमन पर सहयोग बनाने की आवश्यकता है।
- मानव संपर्क और डिजिटल संपर्क सहयोग के नए क्षेत्र हो सकते हैं।